औद्योगिक क्षेत्रों का विकास पीपीपी मोड पर होगा

राज्य मुख्यालय | प्रमुख संवाददाता

राज्य में निजी क्षेत्रों के सहयोग से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। पांच से 50 एकड़ भूमि का स्वामित्व रखने वालों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) लिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही उ.प्र. लघु उद्योग निगम के कर्मियों को छठवां वेतनमान दिए जाने का फैसला भी हुआ है। इस प्रस्ताव को अब अधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

ये फैसले शनिवार को उ.प्र. लघु उद्योग निगम लि. (यूपीएसआईसी) के निदेशक मंडल की 249वीं बैठक में लिए गए। बैठक की अध्यक्षता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने की।

इस बैठक में एमएसएमई इकाइयों को कोयले आपूर्ति में आने वाले कठिनाइयों दूर करने के लिए निगम की कोल योजना के तहत कोल समन्वयक की नियुक्ति के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

स्कूटर इंडिया एन्सिलरी स्टेट नादरगंज लखनऊ और निगम के बीच चले आ रहे 40 वर्ष पुराने भूखंड विवाद का निस्तारण किया गया। अमिय कृष्ण त्रिपाठी सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला सहकारी बैंक फैजाबाद को निगम में उप प्रबंधक सामान्य के पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखने का फैसला हुआ।

बैठक में उपाध्यक्ष श्री राकेश गर्ग, प्रबंध निदेशक यूपीएसआईसी राम यज्ञ मिश्र, निदेशक सामान्य प्रबंधन राजीव कुमार श्रीवास्तव तथा अपर निदेशक कोषागार अजय जौहरी मौजूद थे।

निगम के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन शीघ्र

निगम में रिक्त पदों पर नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति हेतु शासन को अधियाचन भेजने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई। निगम में पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों पर शीघ्र पदोन्नति की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। अपर मुख्य सचिव सहगल ने कहा कि निगम द्वारा एमएसएमई को कच्चे माल जैसे लौह व इस्पात, अलौह धातु, कोयला आदि उपलब्ध कराया जाता है। विपणन सहायता योजना के तहत इकाइयों को आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। इसके लिए प्रदेश के विभिन्न शहरों में निगम के सात क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित है। निगम में क, ख, ग व घ श्रेणी के 395 पद स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष वर्तमान में 87 कार्मिक कार्यरत है। इन पदों पर नियमित नियुक्ति से योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित होगा।